Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 2
November 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Education

भारत में उच्च शिक्षा सुधारों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रभाव का मूल्यांकन

राशिद हुसैन
शिक्षा
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

DECLARATION: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER /ARTICLE, HERE BY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN GENUINE PAPER. IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/OTHER REAL AUTHOR ARISES, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL WEBSITE. FOR THE REASON OF CONTENT AMENDMENT /OR ANY TECHNICAL ISSUE WITH NO VISIBILITY ON WEBSITE /UPDATES, I HAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION.FOR ANY PUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE, I SHALL BE LEGALLY RESPONSIBLE. (COMPLETE DECLARATION OF THE AUTHOR AT THE LAST PAGE OF THIS PAPER/ARTICLE

अमूर्त

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है, जिसमें बहु–विषयक शिक्षा, पाठ्यक्रम लचीलापन, अनुसंधान एकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन और डिजिटल विस्तार पर जोर दिया गया है। यह स्टडी एनईपी 2020 के शुरुआती असर का मूल्यांकन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, एक्रेडिटेशन मैनुअल, एक्सपर्ट एनालिसिस और डिजिटल लर्निंग रिपोर्ट्स से सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल करके एक मिक्स्ड क्वालिटेटिव–क्वांटिटेटिव तरीके से करती है। निष्कर्षों से पता चलता है कि शासन पुनर्गठन, एफवाईयूजीपी और एबीसी जैसे लचीले पाठ्यक्रम मॉडल को अपनाने, परिणाम–आधारित शैक्षणिक प्रथाओं को शामिल करने और डव्व्हे एलएमएस प्लेटफार्मों और मिश्रित शिक्षा के क्रमिक एकीकरण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 110 संस्थानों में मात्रात्मक आवृत्ति–प्रतिशत विश्लेषण पाठ्यक्रम सुधार, शैक्षणिक परिवर्तन और डिजिटल बुनियादी ढांचे में मध्यम अपनाने के स्तर को दर्शाता है, जबकि स्वायत्तता विस्तार, एमईईएस कार्यान्वयन और डिजिटल–विभाजन चिंताओं में लगातार चुनौतियों को उजागर करता है। कुल मिलाकर, परिणाम दर्शाते हैं कि यद्यपि एनईपी 2020 ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार शुरू किए हैं, फिर भी संस्थागत क्षमता, वित्त पोषण और प्रशासनिक तत्परता में असमानताएं कार्यान्वयन परिणामों को आकार दे रही हैं। अध्ययन का निष्कर्ष है कि भारत में समग्र, लचीले और समावेशी उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के एनईपी 2020 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए निरंतर नीति समर्थन, लक्षित क्षमता निर्माण और समानता–संचालित रणनीतियाँ आवश्यक हैं।

कीवर्ड : *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उच्च शिक्षा सुधारय एफवाईयूजीपीय अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्सय बहु प्रवेश और निकास प्रणाली।*

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 2
November 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Education

1. परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, 1986 के बाद से भारत की शिक्षा प्रणाली की सबसे व्यापक पुनर्कल्पना का प्रतिनिधित्व करती है। उच्च शिक्षा के लिए, यह खंडित, विशिष्ट और परीक्षा–संचालित संरचनाओं से बहु–विषयक शिक्षण, लचीले पाठ्यक्रम, अनुसंधान गहनता और परिणाम–आधारित शिक्षा की ओर एक आदर्श बदलाव का प्रस्ताव करती है। प्रमुख उपायों में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूजीपी), अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) के साथ मल्टीपल एंट्री और एग्जिट (एमईईएस), राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के साथ एकीकृत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ), समग्र और बहु–विषयक विश्वविद्यालय, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के माध्यम से हल्का–पर–कड़ा विनियमन, और डिजिटल और मुक्त शिक्षा का विस्तार शामिल हैं।

यह पत्र एक संरचित समीक्षा और भारतीय संस्थानों में प्रारंभिक कार्यान्वयन अनुभवों के गुणात्मक और मात्रात्मक संश्लेषण के माध्यम से उच्च शिक्षा सुधारों पर एनईपी 2020 के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। यह प्रशासन, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, समानता और पहुंच, अनुसंधान और नवाचार, और गुणवत्ता आश्वासन में प्रगति और बाधाओं का आकलन करता हैं।

2. साहित्य समीक्षा

जैन, खरे, गोयल और गोयल (2023) ने पॉलिसी लागू होने से पहले और बाद की संस्थागत स्थितियों की तुलना करके उच्च शिक्षा संस्थानों पर एनईपी 2020 के प्रभाव की जांच की। उनके अध्ययन में यह बात सामने आई कि पॉलिसी लागू होने से एकेडमिक स्ट्रक्चर, करिकुलम डिलीवरी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में काफी बदलाव आया है। लेखकों ने बताया कि संस्थानों ने मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथवे और टेक्नोलॉजी–इनेबल्ड टीचिंग तरीकों को तेजी से अपनाया। उन्होंने यह भी पाया कि हालांकि कई संस्थानों ने पॉलिसी निर्देशों के प्रति सकारात्मक अनुकूलन दिखाया, लेकिन फैकल्टी की तैयारी, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडिंग और सुधारों को समान रूप से लागू करने की संस्थागत क्षमता जैसे क्षेत्रों में चुनौतियां बनी रहीं। उनके तुलनात्मक विश्लेषण से पता चला कि एनईपी 2020 ने सार्थक सिस्टमैटिक बदलाव शुरू किए हैं, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम लगातार कार्यान्वयन प्रयासों पर निर्भर करते हैं।

कुलल एट अल. (2024) ने छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा विशेषज्ञों के दृष्टिकोण को शामिल करके एनईपी 2020 का एक व्यापक मूल्यांकन प्रदान किया। उनके निष्कर्षों से पता चला कि स्टेकहोल्डर्स आम तौर पर इस पॉलिसी को लचीलेपन, कौशल–आधारित शिक्षा और समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रगतिशील मानते हैं। हालांकि, अध्ययन में व्यावहारिक कार्यान्वयन, संसाधन आवंटन और नए शैक्षणिक मॉडल अपनाने के लिए संस्थानों की तैयारी से संबंधित चिंताओं का भी खुलासा हुआ। शोधकर्ताओं ने संकेत दिया कि

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 2
November 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Education

हालांकि पॉलिसी ने परिवर्तनकारी सुधारों का वादा किया था, लेकिन पॉलिसी की आकांक्षाओं और जमीनी वास्तविकताओं के बीच बेमेल होने से स्टेकहोल्डर्स के बीच अनिश्चितता पैदा हुई। उनके विश्लेषण ने इस बात पर जोर दिया कि सफल कार्यान्वयन के लिए संस्थागत स्तर पर कठोर क्षमता निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चरल सहायता और निरंतर निगरानी की आवश्यकता है।

खान (2020) ने एनईपी 2020 का एक वैचारिक अवलोकन प्रस्तुत किया, जिसमें इसके विजन, संरचनात्मक सुधारों और भारत की शिक्षा प्रणाली पर अपेक्षित प्रभाव की रूपरेखा बताई गई। लेखक ने इस बात पर जोर दिया कि पॉलिसी ने मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा, फॉर्मेटिव असेसमेंट और बढ़ी हुई अनुसंधान क्षमताओं की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इस काम में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि एनईपी 2020 का लक्ष्य डिजिटल लर्निंग, व्यावसायिक शिक्षा और मूलभूत साक्षरता उपायों को एकीकृत करके भारतीय शिक्षा को वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करना है। खान के विश्लेषण में संस्थागत स्वायत्तता, फंडिंग आवश्यकताओं और विविध शैक्षिक संदर्भों में राष्ट्रव्यापी अपनाने की व्यवहार्यता के बारे में चिंताओं को भी दर्शाया गया। कुल मिलाकर, अध्ययन ने पॉलिसी के इरादे और इसके द्वारा शुरू किए जाने वाले रणनीतिक सुधारों की एक मूलभूत समझ प्रदान की।

कुरियन और चंद्रमना (2020) ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए एनईपी 2020 के निहितार्थों का विश्लेषण किया। उनके अध्ययन में पाया गया कि पॉलिसी ने डिग्री कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया, शैक्षणिक लचीलेपन को मजबूत किया और परिणाम–आधारित शिक्षा पर जोर दिया। लेखकों ने तर्क दिया कि एनईपी 2020 में एकेडमिक क्वालिटी को बेहतर बनाने, स्टूडेंट मोबिलिटी बढ़ाने और इनोवेशन–ड्रिवन लर्निंग माहौल को बढ़ावा देने की क्षमता है। हालाँकि, उन्होंने यह भी देखा कि इसे लागू करने में कई चुनौतियाँ हैं – खासकर इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी तक पहुँच और फैकल्टी ट्रेनिंग में असमानताएँ – जो बड़ी रुकावटें पैदा करती हैं। उनके असेसमेंट का नतीजा यह निकला कि हालाँकि एनईपी 2020 को एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी के तौर पर बनाया गया था, लेकिन इसकी सफलता काफी हद तक असरदार तरीके से लागू करने और सरकार और संस्थानों से पर्याप्त सपोर्ट पर निर्भर करती है।

3. शोध पद्धति

यह अध्ययन भारत में उच्च शिक्षा सुधारों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रारंभिक प्रभाव की व्यवस्थित रूप से जाँच करने के लिए एक संरचित पद्धतिगत दृष्टिकोण अपनाता है। यह देखते हुए कि नीति कार्यान्वयन के सतत चरण में है, अनुसंधान वर्णनात्मक प्रवृत्तियों और व्याख्यात्मक अंतर्दृष्टि दोनों को पकड़ने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक तरीकों के संयोजन पर निर्भर करता है। यह कार्यप्रणाली आधिकारिक नीति दस्तावेजों, संस्थागत प्रकाशनों, मान्यता ढाँचों और विशेषज्ञ विश्लेषणों से प्राप्त द्वितीयक

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 2
November 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Education

डेटा की आलोचनात्मक जांच पर केंद्रित है। विषयगत दृष्टिकोण से इन सामग्रियों को व्यवस्थित और विश्लेषित करके, अध्ययन का उद्देश्य इस बात की व्यापक समझ विकसित करना है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रशासन, पाठ्यक्रम, डिजिटल शिक्षा, शिक्षणशास्त्र और गुणवत्ता आश्वासन सुधार किस प्रकार सामने आ रहे हैं। यह पद्धतिगत संरचना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 द्वारा आकार दिए जा रहे विकासशील शैक्षिक परिदृश्य के लिए विश्वसनीयता, विश्लेषणात्मक गहराई और प्रासंगिकता सुनिश्चित करती है।

3.1 शोध डिजाइन

वर्तमान अध्ययन भारत में उच्च शिक्षा सुधारों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रारंभिक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक मिश्रित गुणात्मक–मात्रात्मक अन्वेषणात्मक शोध डिजाइन का उपयोग करता है। यह डिजाइन मुख्य रूप से डेस्क–आधारित है, जो द्वितीयक डेटा पर निर्भर है, तथा इसे व्यवसायी टिप्पणियों, नीति नोट्स और संस्थागत रिपोर्टों से प्राप्त गुणात्मक अंतर्दृष्टि द्वारा समर्थित किया गया है। यह दृष्टिकोण उपयुक्त है क्योंकि एनईपी 2020 अभी भी कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में है, और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेज सिस्टम–स्तरीय परिवर्तनों का सबसे विश्वसनीय प्रमाण प्रदान करते हैं।

3.2 डेटा स्रोत

यह अध्ययन उच्च शिक्षा में एनईपी 2020 के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए द्वितीयक डेटा स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है। इन स्रोतों में आधिकारिक नीति दस्तावेज जैसे कि एनईपी 2020 और शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी, एआईसीटीई और अन्य नियामक निकायों द्वारा जारी दिशानिर्देश शामिल हैं। प्रमुख सुधारों से संबंधित संस्थागत विनियमों – जैसे कि चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूजीपी), मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम (एमईईएस), अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी), और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) – की भी समीक्षा की गई। विश्वविद्यालय स्तर की सामग्री, जिसमें पाठ्यक्रम रूपरेखा, संशोधित पाठ्यक्रम, कार्यक्रम संरचना, वार्षिक रिपोर्ट और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन दस्तावेज शामिल हैं, ने संस्थागत प्रथाओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान की।

गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को समझने के लिए एनएएसी और एनबीए मैनुअल, स्व–अध्ययन रिपोर्ट, मूल्यांकन रूब्रिक्स और मान्यता परिणामों जैसे मान्यता–संबंधी संसाधनों की जांच की गई। इसके अतिरिक्त, शैक्षिक लेखों, नीतिगत संक्षिप्त विवरणों, सम्मेलन पत्रों, राय–पत्रों तथा शिक्षा शोधकर्ताओं और थिंक टैंकों की टिप्पणियों के रूप में विशेषज्ञ विश्लेषणों का उपयोग किया गया। डिजिटल शिक्षा पर रिपोर्ट, जिसमें

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 2
November 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Education

एमओओसी पर संस्थागत नीतियां, मिश्रित शिक्षण दिशानिर्देश और शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) डेटा शामिल हैं, ने एनईपी 2020 के तहत डिजिटल परिवर्तन को समझने में और योगदान दिया।

3.3 विश्लेषणात्मक रूपरेखा

इस अध्ययन के लिए विश्लेषणात्मक रूपरेखा एक विषयगत मूल्यांकन मॉडल के आसपास संरचित है, जिसे उच्च शिक्षा संस्थानों में एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की व्यापकता और गहराई दोनों को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रासंगिक द्वितीयक डेटा एकत्र करने के बाद, सामग्री को व्यवस्थित रूप से मुख्य सुधार डोमेन में वर्गीकृत किया गया – शासन पुनर्गठन, पाठ्यक्रम लचीलापन, शैक्षणिक परिवर्तन, मूल्यांकन सुधार, डिजिटल और खुली शिक्षा, गुणवत्ता आश्वासन और समानता–केंद्रित पहल। प्रत्येक दस्तावेज की समीक्षा की गई ताकि इन क्षेत्रों में प्रगति, संस्थागत प्रतिक्रियाओं और उभरती चुनौतियों के विशिष्ट संकेतक निकाले जा सकें।

डेटा का विश्लेषण करने के लिए गुणात्मक विषयगत कोडिंग और मात्रात्मक सारणीकरण के संयोजन का उपयोग किया गया। गुणात्मक विश्लेषण में पैटर्न की पहचान, आवर्ती विषय, नीति संरेखण और संस्थागत परिवर्तन के कथात्मक साक्ष्य शामिल थे। विषयगत निष्कर्षों के लिए मापनीय समर्थन प्रदान करने हेतु मात्रात्मक डेटा को आवृत्ति और प्रतिशत वितरण में परिवर्तित किया गया। इस दोहरे विश्लेषणात्मक दृ ष्टिकोण ने नीति–संचालित परिवर्तनों और संस्था–स्तरीय प्रथाओं दोनों की संतुलित व्याख्या की अनुमति दी, जिससे उच्च शिक्षा क्षेत्र में एनईपी 2020 के सुधारों का व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित हुआ।

4. परिणाम और चर्चा

यह खंड उच्च शिक्षा संस्थानों में एनईपी 2020 के कार्यान्वयन से संबंधित द्वितीयक आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर अध्ययन के निष्कर्षों को प्रस्तुत और व्याख्या करता है। परिणामों को प्रमुख सुधार क्षेत्रों में व्यवस्थित किया गया है, जिनमें शासन पुनर्गठन, पाठ्यक्रम लचीलापन, शैक्षणिक और मूल्यांकन परिवर्तन, डिजिटल और खुली शिक्षा पहल, अनुसंधान और नवाचार प्रथाएं, और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र शामिल हैं। आवृत्ति और प्रतिशत वितरण से प्राप्त मात्रात्मक संकेतक, और गुणात्मक अंतर्दृष्टि दोनों का उपयोग अपनाने की सीमा, उभरते रुझानों और कार्यान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। चर्चा इन निष्कर्षों को एकीकृत करती है ताकि यह व्यापक समझ प्रदान की जा सके कि एनईपी 2020 किस प्रकार आकार ले रहा है।संस्थागत प्रथाएँ और व्यापक उच्च शिक्षा परिदृश्य।

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 2
November 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Education

4.1 शासन और संस्थागत पुनर्गठन

तालिका 4.1, 110 संस्थानों के नमूने के लिए एनईपी 2020 के अंतर्गत शासन और संस्थागत पुनर्गठन से संबंधित प्रतिक्रियाओं का वितरण प्रस्तुत करती है। तालिका में पांच प्रमुख संकेतक शामिल हैं जो दर्शाते हैं कि संरचनात्मक सुधारों को किस हद तक अपनाया गया है। ये संकेतक बहुविषयक ढांचे को अपनाने, शैक्षणिक गतिशीलता का समर्थन करने वाले तंत्र, संस्थागत स्वायत्तता का विस्तार, शैक्षणिक निकायों का पुनर्गठन, तथा पारंपरिक संबद्धता प्रणालियों से दूर संक्रमण के दौरान आने वाली चुनौतियों को मापते हैं।

तालिका 4.1 शासन और संस्थागत पुनर्गठन

गवर्नेंस इंडिकेटर्स	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
मल्टीडिसिप्लिनरी स्कूलों को अपनाना	33	30.00%
क्रेडिट मोबिलिटी/एग्जिट अवार्ड्स को लागू करना	28	25.45%
ऑटोनॉमस स्टेटस का विस्तार	19	17.27%
बोर्ड ऑफ स्टडीज का रीस्ट्रक्चरिंग	14	12.73%
एफिलिएशन को खत्म करने में चुनौतियाँ	16	14.55%

तालिका 1 से पता चलता है कि 30% संस्थानों ने बहुविषयक स्कूलों को अपनाया है, जिससे यह इस श्रेणी में सबसे व्यापक रूप से कार्यान्वित सुधार बन गया है। इससे पता चलता है कि विश्वविद्यालय व्यापक शैक्षणिक एकीकरण की दिशा में संरचनात्मक बदलावों को प्राथमिकता दे रहे हैं। 25.45% संस्थानों द्वारा क्रेडिट मोबिलिटी और एग्जिट अवार्ड को क्रियान्वित किया गया है, जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम (एमईईएस) की निरंतर स्वीकृति को दर्शाता है।

स्वायत्त स्थिति का विस्तार (17.27%) और अध्ययन बोर्डों का पुनर्गठन (12.73%) मध्यम प्रगति दर्शाता है, जो दर्शाता है कि संस्थान धीरे–धीरे विकेन्द्रीकृत निर्णय लेने और अंतर–विषयक शैक्षणिक प्रशासन की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच, 14.55% ने संबद्धता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में चुनौतियों की बात कही, जो प्रशासनिक और नीतिगत बाधाओं को उजागर करता है जो अभी भी पूर्ण कार्यान्वयन में बाधा डाल रहे हैं।

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 2
November 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Education

चित्र 1, तालिका 4.1 में सूचीबद्ध शासन और संस्थागत पुनर्गठन संकेतकों के प्रतिशत वितरण का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। प्रत्येक बार (या खंड) दृश्य रूप से प्रत्येक सुधार क्षेत्र के सापेक्ष अपनाने के स्तर को दर्शाता है, जिससे विभिन्न संस्थानों में कार्यान्वयन की सीमा की स्पष्ट तुलना संभव हो पाती है।

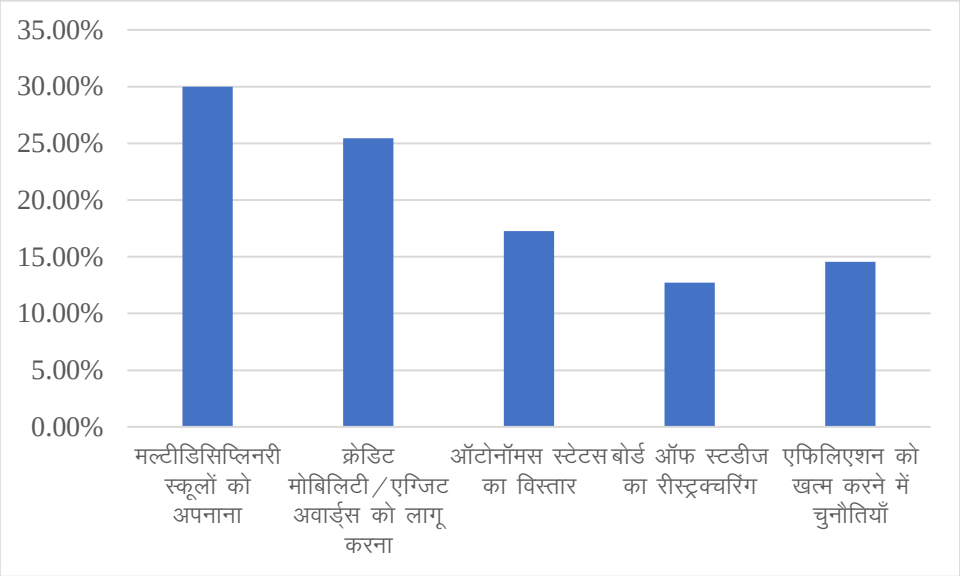

चित्र 1: शासन और संस्थागत पुनर्गठन के प्रतिशत का चित्रमय निरूपण

यह आंकड़ा इस बात पर प्रकाश डालता है कि बहु–विषयक विद्यालयों को अपनाना सबसे प्रमुख शासन सुधार है। यह दृश्य प्रमुखता एनईपी 2020 के बहुविषयक शिक्षा पर जोर के साथ मजबूत संरेखण को दर्शाती है। अगली सर्वोच्च श्रेणी – क्रेडिट मोबिलिटी और एक्जिट अवार्ड – भी ग्राफ के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लेती है, जो लचीले शैक्षणिक मार्गों की ओर संक्रमण के लिए संस्थानों की तत्परता को मजबूत करती है।

स्वायत्तता विस्तार के लिए निम्न स्तर या खंड, अध्ययन बोर्ड का पुनर्गठन, तथा संबद्धता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की चुनौतियां यह संकेत देती हैं कि ये क्षेत्र अभी भी विकसित हो रहे हैं। ग्राफिक पैटर्न इस बात को रेखांकित करता है कि यद्यपि प्रगति शुरू हो गई है, नीति परिवर्तन की जटिलताएं और प्रशासनिक क्षमता में अंतराल सुधार की गति को प्रभावित कर रहे हैं।

4.2 पाठ्यक्रम लचीलापन, एफवाईयूजीपी, और एबीसी

तालिका 4.2 मात्रात्मक डेटा प्रस्तुत करती है जो दर्शाती है कि एनईपी 2020 के तहत पाठ्यक्रम–संबंधी सुधारों को 110 उच्च शिक्षा संस्थानों के नमूने में किस हद तक अपनाया गया है। तालिका में पांच प्रमुख संकेतक शामिल हैं जो चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूजीपी) के कार्यान्वयन की स्थिति, लचीले

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 2
November 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Education

पाठ्यक्रम विकल्पों की उपलब्धता और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) के माध्यम से क्रेडिट गतिशीलता के लिए संस्थागत तत्परता को दर्शाते हैं। इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम (एमईईएस) से जुड़ी चुनौतियों को भी शामिल किया गया है, जो नए कार्यक्रम ढांचे का एक अभिन्न अंग है।

तालिका 4.2 पाठ्यक्रम लचीलापन, एफवाईयूजीपी, और एबीसी

पाठ्यक्रम सुधार संकेतक	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
एफवाईयूजीपी को अपनाना	24	21.82%
प्रमुख–लघु संयोजन प्रस्तावित	23	20.91%
शैक्षणिक क्रेडिट बैंक कार्यान्वित	19	17.27%
बहुविषयक ऐच्छिक उपलब्ध	23	20.91%
मीस कार्यान्वयन में चुनौतियाँ	21	19.09%

तालिका 2 दर्शाती है कि 21.82% संस्थानों ने एफवाईयूजीपी संरचना को पूरी तरह से अपना लिया है, जो यह दर्शाता है कि यद्यपि सुधार प्रगति पर हैं, फिर भी कई संस्थान अभी भी नए शैक्षणिक मॉडल में परिवर्तन कर रहे हैं। प्रमुख–लघु संयोजन और बहु–विषयक ऐच्छिक दोनों ही 20.91% पर लगभग समान अपनाने के स्तर को दर्शाते हैं, जो यह दर्शाता है कि लचीले शिक्षण मार्ग प्रदान करने वाले संस्थानों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (17.27%) का कार्यान्वयन मध्यम प्रगति को दर्शाता है, क्योंकि कई संस्थान अपनी आंतरिक शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचे के साथ संरेखित करना जारी रखे हुए हैं। अंत में, 19.09% संस्थानों ने मीस को लागू करने में चुनौतियों की रिपोर्ट की, जिसमें सलाह प्रणाली, पाठ्यक्रम संरेखण और प्रशासनिक तत्परता जैसी व्यावहारिक चिंताओं पर प्रकाश डाला गया।

चित्र 2, तालिका 4.2 में प्रस्तुत पाठ्यक्रम सुधार संकेतकों के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। प्रत्येक बार (या पाई–चार्ट खंड) एक संकेतक से मेल खाता है, जिससे एफवाईयूजीपी के अपनाने के स्तर, क्रेडिट बैंकिंग तंत्र, प्रमुख–लघु संरचनाओं, बहु–विषयक ऐच्छिक और संस्थानों में मीस से संबंधित चुनौतियों की स्पष्ट तुलना की अनुमति मिलती है।

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 2
November 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Education

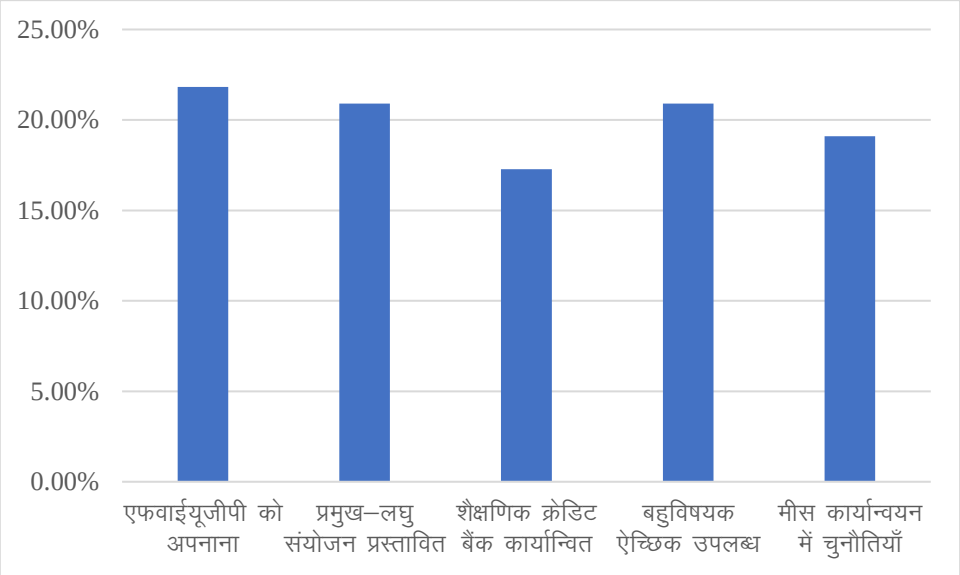

चित्र 2: करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी, एफवाईयूजीपी, और एबीसी के प्रतिशत का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन

ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिकुलम से जुड़े सुधारों का काफी हद तक एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। एफवाईयूजीपी को अपनाना दूसरे इंडिकेटर्स की तुलना में थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन अंतर कम हैं, जिससे पता चलता है कि संस्थान एक समान और कोऑर्डिनेटेड तरीके से करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी को अपना रहे हैं। मल्टीडिसिप्लिनरी इलेक्टिव और मेजर–माइनर कॉम्बिनेशन इसके ठीक बाद आते हैं, जो सिस्टम के होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड लर्निंग पाथवे की ओर बदलाव को दिखाते हैं।

एफवाईयूजीपी या इलेक्टिव पेशकशों की तुलना में एबीसी के इम्प्लीमेंटेशन का कम अनुपात, नेशनल–लेवल क्रेडिट ट्रांसफर मैकेनिज्म को अपनाने में शामिल एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्नोलॉजिकल जटिलता को उजागर करता है। इस बीच, यह आंकड़ा मीस से संबंधित चुनौतियों की रिपोर्ट करने वाले संस्थानों के अनुपात को भी दिखाता है, इस बात पर जोर देता है कि जबकि सुधार चल रहे हैं, सुचारू इम्प्लीमेंटेशन के लिए व्यावहारिक बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए।

4.3 पेडागॉजी, असेसमेंट और लर्निंग आउटकम

तालिका 4.3 एनईपी 2020 से प्रेरित पेडागॉजिकल और असेसमेंट सुधारों को अपनाने को दर्शाने वाला संस्थान–स्तरीय डेटा प्रस्तुत करती है। संकेतक परिणाम–आधारित शिक्षा निरंतर मूल्यांकन रणनीतियों, नवीन मूल्यांकन उपकरणों और माइक्रो–क्रेडेंशियल के उभरते उपयोग के एकीकरण की सीमा को उजागर करते हैं। तालिका उन चुनौतियों को भी दर्शाती है जिनका सामना संस्थानों को नए मूल्यांकन तरीकों को लागू करने में करना पड़ता है।

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 2
November 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Education

तालिका 4.3 शिक्षणशास्त्र, मूल्यांकन और सीखने के परिणाम

संकेतक	आवृत्ति	प्रतिशत
पाठ्यक्रमों में पीओ और सीओ निर्दिष्ट किए गए हैं	28	25.45%
रूब्रिक और परियोजना–आधारित मूल्यांकन का उपयोग	25	22.73%
निरंतर आंतरिक मूल्यांकन लागू किया गया	24	21.82%
सूक्ष्म–प्रमाणपत्रों का उपयोग	13	11.82%
मूल्यांकन संबंधी चुनौतियों की सूचना दी गई	20	18.18%

तालिका से पता चलता है कि सबसे अधिक सुधार कार्यक्रम परिणामों (पीओ) और पाठ्यक्रम परिणामों (सीओ) के विनिर्देशन में 25.45% दर्ज किया गया है, जो परिणाम–आधारित शिक्षा की ओर मजबूत प्रगति को दर्शाता है। रूब्रिक्स और परियोजना–आधारित मूल्यांकन (22.73%) का उपयोग और सतत आंतरिक मूल्यांकन (21.82%) का कार्यान्वयन इसके ठीक बाद आता है, जो पारंपरिक रटंत–आधारित मूल्यांकन से अधिक प्रामाणिक और योग्यता–संचालित मूल्यांकन प्रथाओं की ओर एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है।

माइक्रो–क्रेडेंशियल्स का उपयोग (11.82%) तुलनात्मक रूप से कम है, जो बताता है कि यह नवाचार अभी भी उभर रहा है और इसके लिए आगे संस्थागत क्षमता निर्माण और डिजिटल एकीकरण की आवश्यकता होगी। इस बीच, 18.18% संस्थानों ने मूल्यांकन सुधारों में चुनौतियों की सूचना दी, जो संकाय की तैयारी, रूब्रिक डिजाइन, बड़े कक्षा आकार और डिजिटल वातावरण में शैक्षणिक अखंडता से संबंधित चिंताओं को दर्शाती है।

चित्र 3, तालिका 4.3 में सूचीबद्ध प्रमुख शैक्षणिक और मूल्यांकन संकेतकों के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। प्रत्येक बार (या चार्ट खंड) एक सुधार आयाम का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे पीओध्सीओ के सापेक्ष अपनाने के स्तर, रूब्रिक–आधारित मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन, माइक्रो–क्रेडेंशियल उपयोग और मूल्यांकन–संबंधी चुनौतियों की तुलना करना आसान हो जाता है।

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 2
November 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Education

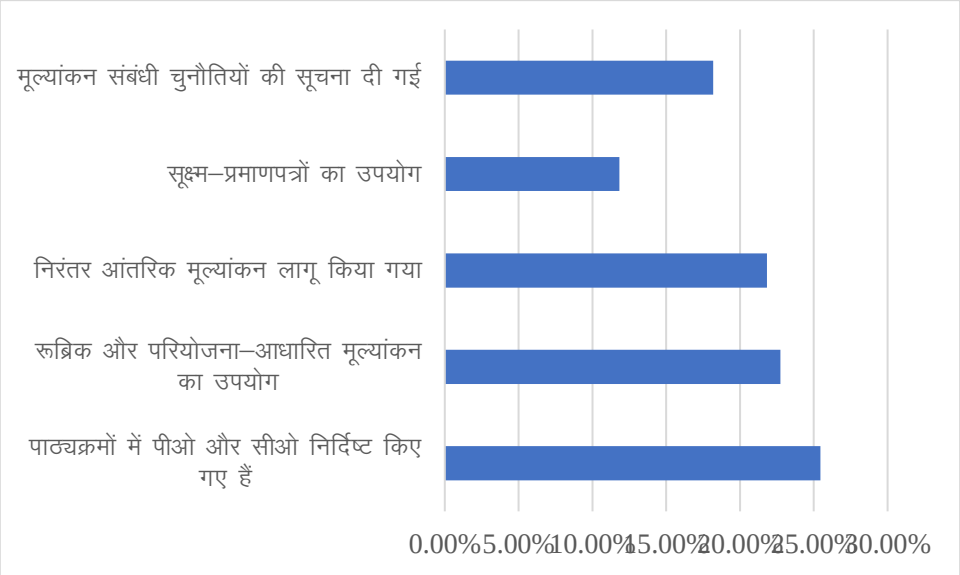

चित्र 3: शिक्षणशास्त्र, मूल्यांकन और अधिगम परिणामों के प्रतिशत का चित्रमय निरूपण

यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पीओ और सीओ विनिर्देशन सबसे अधिक अपनाया जाने वाला सुधार है, जिसके बाद रूब्रिक–आधारित और सतत मूल्यांकन का स्थान आता है। इन संकेतकों को दर्शाने वाले बार की मध्यम ऊंचाई, एनईपी 2020 के तहत निर्धारित परिणाम–केंद्रित शिक्षण और सीखने की ओर बदलाव को स्पष्ट रूप से पुष्ट करती है। माइक्रो–क्रेडेंशियल्स के लिए काफी कम बार यह दर्शाता है कि अभी भी इसका उपयोग सीमित है, जो भारतीय उच्च शिक्षा में डिजिटल क्रेडेंशियल इकोसिस्टम के प्रारंभिक चरण से मेल खाता है।

मूल्यांकन चुनौतियों का प्रतिनिधित्व यह दर्शाता है कि सुधार तो प्रगति पर हैं, लेकिन संस्थाएं कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं से जूझ रही हैं। समग्र ग्राफिक पैटर्न से पता चलता है कि शैक्षणिक सुधार चल रहे हैं, लेकिन पूर्ण प्रभाव प्राप्त करने के लिए निरंतर संकाय प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधन विस्तार और सुव्यवस्थित मूल्यांकन ढांचे की आवश्यकता है।

4.4 डिजिटल और मुक्त शिक्षण

तालिका 4.4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत डिजिटल और मुक्त शिक्षण सुधारों को संस्थागत रूप से अपनाने के मात्रात्मक वितरण को दर्शाती है। तालिका में उच्च शिक्षा संस्थानों में हो रहे डिजिटल परिवर्तन को दर्शाने वाले पाँच प्रमुख संकेतक शामिल हैं। इनमें बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (एमओओसी) का बढ़ता उपयोग, मिश्रित या हाइब्रिड शिक्षण मॉडल को अपनाना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) का कार्यान्वयन, डिजिटल शैक्षणिक भंडारों की उपलब्धता और डिजिटल विभाजन के कारण अनुभव की जाने वाली चुनौतियाँ शामिल हैं।

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 2
November 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Education

तालिका 4.4 डिजिटल और मुक्त शिक्षा

संकेतक	आवृत्ति	प्रतिशत
एमओओसी का उपयोग बढ़ा	27	24.55%
मिश्रित/हाइब्रिड वितरण को अपनाया गया	22	20.00%
एलएमएस प्लेटफॉर्म लागू किए गए	28	25.45%
डिजिटल रिपॉजिटरी उपलब्ध	15	13.64%
डिजिटल डिवाइड चुनौतियों की सूचना दी गई	18	16.36%

तालिका के अनुसार, एलएमएस प्लेटफार्मों का कार्यान्वयन सबसे अधिक 25.45% है, जो दर्शाता है कि संस्थान अनुदेशात्मक वितरण और मूल्यांकन के लिए केंद्रीकृत डिजिटल शिक्षण प्रबंधन को प्राथमिकता दे रहे हैं। डव्ब्े (24.55%) का उपयोग इसके ठीक बाद आता है, जो दर्शाता है कि संस्थान कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को पूरक बनाने और उन्नत सामग्री तक पहुंच का विस्तार करने के लिए बाहरी रूप से विकसित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का तेजी से लाभ उठा रहे हैं।

मिश्रित/हाइब्रिड वितरण मॉडल (20.00%) को अपनाने से मिश्रित शिक्षण दृष्टिकोणों का स्थिर एकीकरण, आमने–सामने और ऑनलाइन शिक्षण का संयोजन दिखाई देता है। डिजिटल रिपॉजिटरी की उपलब्धता (13.64%) तुलनात्मक रूप से कम बनी हुई है, जिसका अर्थ है कि कुछ संस्थानों में अभी भी डिजिटल शिक्षण सामग्री, शोध आउटपुट और संग्रहीत संसाधनों के लिए संस्थागत रिपॉजिटरी का अभाव है।

इसके अलावा, 16.36% संस्थानों ने डिजिटल विभाजन चुनौतियों की सूचना दी, जो छात्रों और संकाय के बीच इंटरनेट पहुंच, डिवाइस की उपलब्धता और डिजिटल योग्यता में लगातार असमानताओं को दर्शाती है।

चित्र 4, तालिका 4.4 में प्रस्तुत डिजिटल और मुक्त शिक्षण संकेतकों के प्रतिशत वितरण को दृश्यात्मक रूप से प्रदर्शित करता है। प्रत्येक बार (या चार्ट खंड) डिजिटल परिवर्तन के एक आयाम का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत अपनाने की दरों की आसानी से दृश्य तुलना की जा सकती है।

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 2
November 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Education

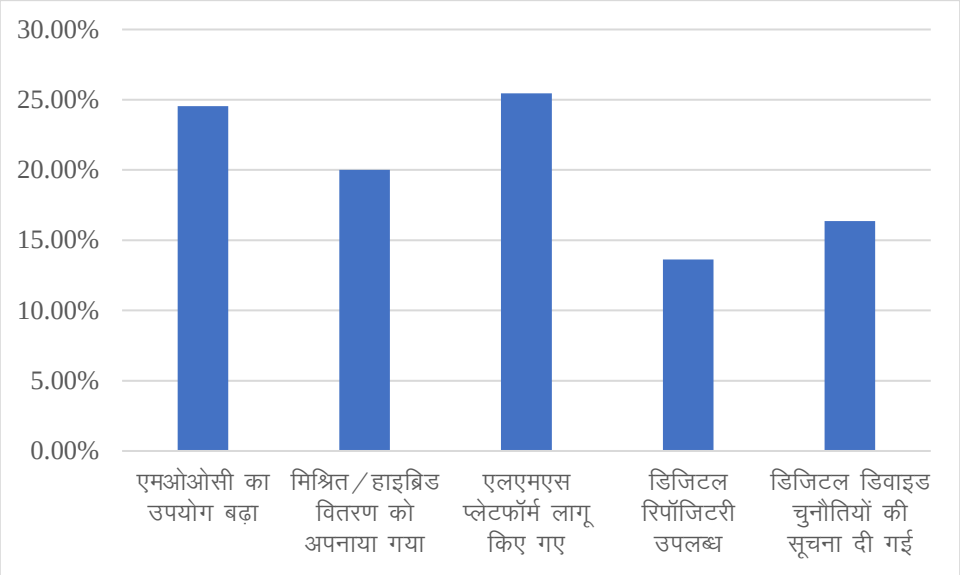

चित्र 4: डिजिटल और मुक्त शिक्षा के प्रतिशत का चित्रमय निरूपण

चित्रमय निरूपण इस बात पर प्रकाश डालता है कि एलएमएस कार्यान्वयन और एमओओसी उपयोग, दो सबसे प्रमुख रूप से अपनाए गए डिजिटल शिक्षण सुधार हैं, जैसा कि चित्र में सबसे ऊँची पट्टियों द्वारा दर्शाया गया है। यह संरचित डिजिटल शिक्षण वातावरण और ऑनलाइन शिक्षण विकल्पों के माध्यम से शैक्षणिक लचीलेपन को बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास को दर्शाता है।

मिश्रितध्हाइब्रिड मोड और डिजिटल डिवाइड चुनौतियों को दर्शाने वाली पट्टियां मध्यम ऊंचाई की दिखाई देती हैं, जो लगातार चुनौतियों के साथ–साथ बढ़ते अनुकूलन को दर्शाती हैं। सबसे छोटी पट्टी डिजिटल रिपोजिटरी उपलब्धता को दर्शाती है, जो इस बात को पुष्ट करती है कि रिपोजिटरी विकास अभी भी एक उभरती हुई प्रक्रिया है।

5. निष्कर्ष

इस अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि एनईपी 2020 ने संरचनात्मक आधुनिकीकरण, पाठ्यचर्या नवाचार और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देकर भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को नया रूप देना शुरू कर दिया है। संस्थाएं बहुविषयक ढांचे, लचीली कार्यक्रम संरचनाओं जैसे कि एफवाईयूजीपी और मीस, तथा परिणाम–आधारित मूल्यांकन प्रथाओं को अपना रही हैं, साथ ही डव्ब्े, एलएमएस प्लेटफार्मों और मिश्रित शिक्षा के उपयोग का विस्तार कर रही हैं। इन सकारात्मक प्रगति के बावजूद, विश्लेषण से संस्थानों में असमान प्रगति का पता चलता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां मजबूत प्रशासनिक क्षमता, तकनीकी बुनियादी ढांचे और निरंतर वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है। ऋण गतिशीलता, मूल्यांकन गुणवत्ता, स्वायत्तता विस्तार और डिजिटल विभाजन से संबंधित चुनौतियां एकसमान कार्यान्वयन में बाधा बन रही

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 2
November 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Education

हैं। एनईपी 2020 को अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए, संस्थानों को क्षमता निर्माण, प्रभावी छात्र सहायता प्रणाली और समान डिजिटल पहुंच को प्राथमिकता देनी होगी, जबकि नियामक निकाय सुसंगतता और स्थिर वित्तपोषण सुनिश्चित करेंगे। कुल मिलाकर, हालांकि एनईपी 2020 का प्रारंभिक प्रभाव आशाजनक है, इसकी दीर्घकालिक सफलता सुसंगत नीति कार्यान्वयन, सहयोगात्मक शासन और समावेशी, छात्र–केंद्रित शैक्षिक परिवर्तन के लिए निरंतर प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है।

संदर्भ

1. *ऐथल, एस., और ऐथल, एस. (2020). भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में उच्च शिक्षा के कार्यान्वयन की रणनीतियाँ।*
2. *बनर्जी, एन., दास, ए., और घोष, एस. (2021). राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)रू एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। टुवर्ड्स एक्सीलेंस, 13(3), 406–420।*
3. *जैन, एस., खरे, ए., गोयल, ओ., और गोयल, पी. (2023). भारत में उच्च शिक्षा पर एनईपी 2020 का प्रभावरू नीति के कार्यान्वयन से पहले और बाद में चुनिंदा शैक्षणिक संस्थानों का एक तुलनात्मक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, 11(5), ी349–ी360।*
4. *जोशी, एम. (2023). अंतर्राष्ट्रीयकरण को सशक्त बनानारू भारत में उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। जर्नल ऑफ डेटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग, 38(2), 4436।*
5. *केसी, टी. (2022). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उच्च शिक्षा पर प्रभाव। सुमेधा जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, 11(2), 27–35।*
6. *खान, एम. जी. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020।*
7. *कुलाल, ए., एन, ए., दिनेश, एस., भट, डी. सी., और गिरीश, ए. (2024). भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के वादों और कमियों का मूल्यांकनरू छात्रों, शिक्षकों और विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से अंतर्दृष्टि। सेज ओपन, 14(4), 21582440241279367।*
8. *कुमार, के., प्रकाश, ए., और सिंह, के. (2021). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में भविष्य की पीढ़ी को बदलने के लिए एक मार्गदर्शक कैसे हो सकती है। जर्नल ऑफ पब्लिक अफेयर्स, 21(3), म2500।*
9. *कुरियन, ए., और चंद्रमना, एस. बी. (2020). नई शिक्षा नीति 2020 का उच्च शिक्षा पर प्रभाव। आत्मनिर्भर भारतरू आत्मनिर्भर भारत के लिए एक रोडमैप।*
10. *नंदी, ए. (2023). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020–शैक्षिक प्रणाली पर चुनौतियाँ और अवसर। प्श्रथ्डत्–इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, 5(3).*

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 2
November 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Education

11. *पंडितराव, एम. एम., और पंडितराव, एम. एम. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020रू इसमें एक छात्र, एक माता–पिता, एक शिक्षक, या हमारे लिए, एक उच्च शिक्षा संस्थानधविश्वविद्यालय के रूप में क्या है? आदेश विश्वविद्यालय जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, 2(2), 70–79.*
12. *सार्ता, ए. (2022). राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020)रू भारत में स्कूल और उच्च शिक्षा में होने वाले सुधारों पर एक विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज, 11(3), 103–113.*
13. *सेनापति, आर., और सिंह, एस. के. (2023). राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 और उच्च शिक्षा में मूल्यांकन सुधाररू 21वीं सदी के भारत के लिए परिवर्तन की कल्पना। श्यूनिवर्सिटी न्यूजश का विशेष अंक, 61, 21.*
14. *उमाचगी, ए. ई., और सेल्वी, आर. (2022). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उच्च शिक्षारू एक संक्षिप्त समीक्षा। सुमेधा जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, 11(2), 3456–3460.*
15. *यादव, एम. एस., और यादव, एम. के. (2023). भारतीय एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा शैक्षणिक संवर्धन नीतियों का निहित प्रभावरू चुनौतियाँ, पाठ्यक्रम, दृष्टिकोण, अवसर और कार्यान्वयन। अमेरिकन जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, 1(4), 1–12.*

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 2
November 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Education

Author's Declaration

I as an author of the above research paper/article, here by, declare that the content of this paper is prepared by me and if any person having copyright issue or patent or anything otherwise related to the content, I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website /amendments /updates, I have resubmitted my paper for publication on the same date. If any data or information given by me is not correct, I shall always be legally responsible. With my whole responsibility legally and formally have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (if any) or expert to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and hentriacontane is genuinely mine. If any issue arises related to Plagiarism/ Guide Name/ Educational Qualification /Designation /Address of my university/ college/institution/ Structure or Formatting/ Resubmission /Submission /Copyright /Patent /Submission for any higher degree or Job/Primary Data/Secondary Data Issues. I will be solely/entirely responsible for any legal issues. I have been informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the database due to some technical fault or hacking and therefore the process of resubmission is there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents (Andhra/Driving License/Any Identity Proof and Photo) in spite of demand from the publisher then my paper maybe rejected or removed from the website anytime and may not be consider for verification. I accept the fact that as the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that if publisher finds Any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper maybe removed from the website or the watermark of remark/actuality maybe mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against me.

राशिद हुसैन

******